Golden Research Thoughts
ISSN 2231-5063
Impact Factor : 2.2052 (UIF)
Volume-4 | Issue-5 | Nov-2014 Available online at www.aygrt.isrj.org

भ्रष्टाचार और वर्तमान राजनीति में काले धन का मुकाबला अंतर्वस्तु विश्लेषणात्मक अध्ययन

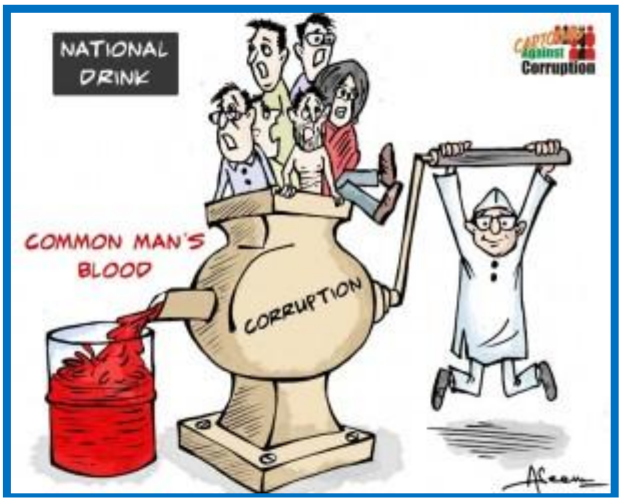

नेहा नेमा

शोधार्थी पीएच् ,डी, अहिंसा एवं शांति अध्ययन विभाग , महात्मा गांधी अंतराष्ट्रीय हिंदी विष्वविद्यालय वर्धा (महाराष्ट्र)

सारांश— आख़िर क्या है यह काला धन, इसका इतिहास और कैसे वापस आ सकता है यह काला धन?
भारत को इस संदर्भ में बहुत सजग होकर काम करना होगा। सवाल यही है कि क्या वह इस दिशा में एक ऐसे वैश्विक गठबंधन का हिस्सा बनना चाहता है, जिसके तहत सहज रूप से ऐसी सूचनाओं को साझा किया जाना है अथवा नहीं। क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सूचनाओं के पक्ष में पर्याप्त साक्ष्य और प्रमाण हों अथवा हम केवल नारेबाजी तक सीमित रहना चाहते हैं? बर्लिन में तकरीबन 50 देशों के साथ एक हालिया बैठक में भारत भाग नहीं ले सका, क्योंकि भारत में यह प्रचलित धारण है कि गोपनीयता के प्रावधान भारतीय कानून के में असंवैधानिक हैं। इस दृष्टिकोण पर नए सिरे से विचार किए जाने की आवश्यकता है। विदेशों

Golden Research Thoughts
ISSN 2231-5063
Impact Factor : 2.2052 (UIF)
Volume-4 | Issue-5 | Nov-2014 Available online at www.aygrt.isrj.org

में जमा धन के बारे में सूचनाओं का सहज ~~आदान~~ प्रदान धन के अधिकृत और अनधिकृत दोनों ही तरह के लेन देन से जुड़ा हुआ है। पैसे के कानूनी लेन देन के संबंध में कोई जानकारी क्यों सार्वजनिक की जानी चाहिए? इसी तरह राजनीतिक अथवा किसी अन्य उद्देश्य से गैर कानूनी लेन देन की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए|

प्रस्तावना

अरुण जेटली के विचार मेरे द्वारा सुने गये विचार फिर काले धन पर समझ बनाने की कोशिश की गई है | कर चोरी के सुरक्षित ठिकाने माने जाने वाले देशों में जमा किए गए अवैध धन अथवा विदेशी धरती पर किए गए इस तरह के अन्य लेन देन को लेकर आज विश्व समुदाय अधिक संगठित और सुव्यवस्थित तरीके से प्रयासरत है। पहले कर चोरी के स्वर्ग माने जाने वाले देश काले धन के मामले में किसी भी तरह का सहयोग नहीं करते हैं, लेकिन अब इस मामले में कुछ देशों पर अंतरराष्ट्रीय दबाव डाला गया है कि वे काला धन रखने वाले खाता धारकों के मामले में अपनी पूर्व की नीतियों में ढिलाई बरतें और इनका खुलासा करते हुए संबंधित देशों की सरकारों के साथ सहयोग करें। तकरीबन वे सभी देश जिन्होंने डीटीए या दोहरा कराधान बचाव संधि कर रखी है अथवा अमेरिका की तरह अपने यहां ऐसा कोई घरेलू कानून बना रखा है वहां की सरकारों के साथ गोपनीयता के प्रावधान के साथ काले धन की कोई सूचना अथवा जानकारी साझा की जा सकती है। गोपनीयता संबंधी इस प्रावधान के तहत नाम का खुलासा तभी किया जा सकता है जब किसी अदालत में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमे की प्रक्रिया आरंभ हो जाए। इस प्रकार मामला यह नहीं है कि क्या नाम का खुलासा किया जा सकता है, बल्कि यह है कि ऐसा कब किया जा सकता है। बहस का विषय गोपनीय सूचनाओं के खुलासे अथवा उन्हें गोपनीय बनाए रखने के बीच नहीं है, बल्कि यह कर संधियों का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत खुलासे और कर संधियों के अनुरूप खुलासे के बीच है। कर समझौते के उल्लंघन के साथ खुलासे में यह शामिल है कि यह काम समानांतर उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इस तरह के खुलासों के साथ आम तौर पर सुबूत अथवा प्रमाण नहीं होते हैं, लेकिन यदि यह खुलासा न्यायालय में आपराधिक मामले में चार्जशीट अथवा आरोप के संदर्भ में किया जाता है तो ऐसे किसी भी खुलासे के साथ पर्याप्त साक्ष्य और प्रमाण भी होते हैं। कर समझौते के उल्लंघन के साथ किया जाने वाला खुलासा खाता धारकों को मदद पहुंचा सकता है। इन मामलों से जुड़े देश इस तरह की किसी भी बात को कर समझौते का उल्लंघन करार देंगे और आगे किसी भी तरह का साक्ष्य अथवा प्रमाण देने से मना कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रमाण और संबंधित देशों

की तरफ से सूचना की पुष्टि के अभाव में अनधिकृत खाताधारकों को किसी भी जांच अथवा अभियोग के मामले में लाभ की स्थिति हासिल होगी और वे खुद के दोषमुक्त घोषित होने का दावा करेंगे। अपरिपक्व खुलासे से खाताधारकों को पहले से ही इस संदर्भ में जरूरी कागजात तैयार करने के लिए सजग और सावधान होने का मौका मिलेगा। यहां तक कि उन्हें साक्ष्यों को मिटाने का भी मौका मिलेगा।

अमेरिका ने एक कानून का निर्माण किया है। इस कानून यानी विदेशी खाते से संबंधित टैक्स मंजूरी अधिनियम 2010 (एफएटीसीए) में गोपनीयता का प्रावधान है। यह विदेशी वित्तीय संस्थानों के लिए यह अनिवार्य करता है कि वह समुचित प्राधिकारी के समक्ष सूचनाएं दर्ज करें और उन्हें साझा भी करें। विदेशी वित्तीय संस्थानों के लिए अमेरिका की आतंरिक राजस्व सेवा के साथ समझौता करना अनिवार्य होगा। इसी कड़ी के तहत विदेशी सरकारें अमेरिकी सरकार के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकती हैं। गोपनीयता के प्रावधान के साथ सूचनाओं का अनिवार्य लेन देन आवश्यक होगा। एफएटीसीए के प्रावधान के मुताबिक इस अधिनियम की शर्तों का पालन नहीं करने वाले देशों में हठी विदेशी वित्तीय संस्थानों पर मूल भुगतान पर तीस प्रतिशत के बराबर टैक्स कटौती की जा सकती है। इस तरह की तीस प्रतिशत की कटौती को अन्य एफएटीसीए अनुपालक देशों द्वारा अधिनियम से बाहर के देशों पर भी लागू किया जाएगा। एफएटीसीए के तहत अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर न करने के परिणाम अनर्थकारी होंगे। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के हमारी सरकार के प्रयास कुल मिलाकर निष्प्रभावी होंगे।

रिजर्व बैंक ने भारत सरकार को पहले ही सूचित कर दिया है कि भारत द्वारा एफएटीसीए का अनुपालन न करने के कितने गंभीर परिणाम होंगे। अनेक देश अब तक इसके दायरे में शामिल हो चुके हैं। सूचना का गैर अधिकृत खुलासा किसी काम का नहीं है। न तो जांच के लिहाज से इसका कोई महत्व है और न ही आर्थिक लाभ की दृष्टि से। इसके विपरीत इस तरह के खुलासे जांच की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनके चलते कुछ तरह की पाबंदियां लग सकती हैं, जो टैक्स कटौती अथवा उसे रोके रखने के रूप में सामने आ सकती हैं। यह स्पष्ट है कि जब चयन गैरअधिकृत खुलासे और संधि के अनुरूप खुलासे के बीच करना है तो बाद वाला विकल्प कहीं अधिक उचित, निष्पक्ष और आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है। इससे सुबूत एकत्र करने में भी मदद मिल सकती है और कानून के साथ कुछ गलत किए जाने का खुलासा भी हो सकता है। सबूत के बिना खुलासे का मतलब होगा कि सबूत कभी उपलब्ध नहीं हो सकेगा। किसी को भी संधि के उल्लंघन के साथ खुलासे की मांग क्यों करनी चाहिए, जबकि उसे इस विषय की अच्छी खासी समझ भी हो। कांग्रेस नहीं चाहती है कि विशेष जांच

दल यानी एसआइटी के पास जो नाम हैं उनके पक्ष में सबूत आएं। मुझे विश्वास है कि जिस एसआइटी को सुप्रीम कोर्ट ने जांच का काम सौंपा है वह मामले के सभी पहलुओं को भलीभांति समझते हुए सच्चाई को सामने लाने में सफल रहेगी। इस मामले में राजग सरकार का रिकार्ड बहुत शानदार रहा है। सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में जो पहला फैसला लिया गया था वह एसआइटी गठित करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को स्वीकार करने का था। सरकार ने 27 जून 2014 को ही एसआइटी का गठन कर दिया था। सच्चाई की तलाश में एसआइटी को सरकार का पूरा समर्थन आगे भी जारी रहेगा।

भारत में काले धन की हक़ीक़त..मैंने जब आशुतोष मिश्रा की विश्लेषण रिपोर्ट को पढ़ा ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल इंडिया रिपोर्ट उन्होंने काले धन की कहानी क्या बताई है तब भारत में कुछ मात्रा में जाहिर है काले धन का मुद्दा पिछले कुछ सालों से भारतीय राजनीति में छाया हुआ दावो हैं उठाने का दौर लगातार जारी हहैं है सवाल वापसी को लेकर दारवा इसकी मात्रा आख़िर क्या है यह काला धन, इसका इतिहास और कैसे वापस आ सकता है यह काला धन?

A. काला धन क्या है?

काला धन दरअसल, वह आय है जिस पर टैक्स की देनदारी बनती है, लेकिन इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को नहीं दी जाती.

ऐसा धन न केवल इस मायने में घातक है कि यह विदेशों में जमा हो, बल्कि इसका इस्तेमाल आतंकवाद, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और आने वाले समय में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता पैदा करने के लिए हो सकता है.

B. भारत में काले धन का इतिहास

भारत में काला धन 1970 के दशक से ही सुर्ख़ियों में बना रहा है. 80 के दशक में बोफ़ोर्स घोटाले के बाद इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाया जाने लगा. इसके बाद, हर चुनाव में राजनेता काले धन के बारे में बात करते रहे हैं.

Golden Research Thoughts
ISSN 2231-5063
Impact Factor : 2.2052 (UIF)
Volume-4 | Issue-5 | Nov-2014 Available online at www.aygrt.isrj.org

2009 और 2014 के आम चुनावों में भाजपा ने इस मुद्दे को पूरी ताक़त से उठाया और उसे इस पर बाबा रामदेव समेत समाज के कई तबक़ों से समर्थन मिला. राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए इस मुद्दे को आसान भाषा में लोगों के सामने पेश किया गया, लेकिन यह उतना आसान नहीं है, जैसा कि दिखता है. काले धन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली गई, हिचकिचाहट के बावजूद न्यायपालिका के आदेश पर सरकार को इस मुद्दे पर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करना पड़ा.

अब सरकार ने विदेशी बैंकों के 627 खातेधारकों के नाम सुप्रीम कोर्ट को बताए हैं. कुछेक खाताधारकों को छोड़कर सरकार ने सूची में शामिल लोगों के नाम उजागर नहीं किए हैं और इसकी वजह वही बताई है जो कि यूपीए सरकार ने बताई थी.

C. *डीटीएए पर रुख़ सही नहीं*

सरकार का कहना है कि खातेधारकों का नाम उजागर करने से अंतरराष्ट्रीय दोहरा कराधान बचाव संधि (डीटीएए) का उल्लंघन होगा. लेकिन हक़ीक़त यह नहीं है.
ये नाम सरकार को फ़्रांस और जर्मनी की सरकारों से मिले हैं न कि डीटीएए के माध्यम से. हर आज़ाद देश को अधिकार है कि उन नामों को उजागर करे जिन्होंने कर चोरी की है.

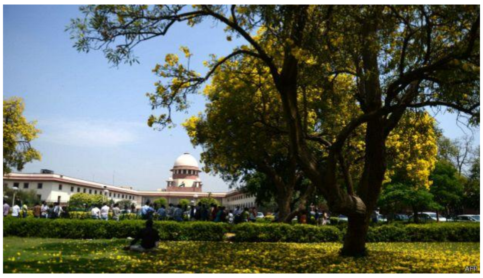

पूर्ववर्ती और मौजूदा सरकारों ने विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के संजीदा प्रयासों के बजाय इसे राजनीतिक भभकी के रूप में इस्तेमाल किया है.

Golden Research Thoughts
ISSN 2231-5063
Impact Factor : 2.2052 (UIF)
Volume-4 | Issue-5 | Nov-2014 Available online at www.aygrt.isrj.org

काले धन के स्रोत का पता लगाना इसका निवेश या इसे बैंकों में जमा करना काफ़ी जटिल मुद्दा है.

D. *पता लगाना मुश्किल*

स्विटज़रलैंड और लिचटेंस्टीन में जमा काले धन का पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में निवेश की दिशा में बदलाव आया है और इसका रुख़ मध्य पूर्व देशों और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की तरफ़ हो गया है.

विदेशी बैंकों के 627 खाताधारकों के नामों की सूची हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी कि काले धन की जानकारी किसी को नहीं है, इसलिए यह कितना होगा, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है.

इसकी वजह यह है कि यह संबंधित देशों के रुख़ पर निर्भर करता है और यह भी सारे विदेशी खातों को ग़ैरक़ानूनी खातों की सूची में नहीं डाला जा सकता.

E. *रणनीति का अभाव*

ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के पास काले धन पर अंकुश लगाने की कोई रणनीति नहीं है. यहां तक कि भारत में काले धन के निवेश पर भी. चाहे यह बैंकों में रखा गया हो या रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी में लगाया गया हो.

घरों की क़ीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी काले धन का ही परिणाम है.

कई स्टिंग ऑपरेशंस में भी इस बात का ख़ुलासा हुआ है कि काले धन को किस तरह से भारतीय बैंकों, शेयर बाज़ार और उद्योगों में लगाया गया है.

Golden Research Thoughts
ISSN 2231-5063
Impact Factor : 2.2052 (UIF)
Volume-4 | Issue-5 | Nov-2014 Available online at www.aygrt.isrj.org

इस समस्या से निपटने के लिए लंबी अवधि की रणनीति बनाए जाने की ज़रूरत है. इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि हम काले धन के स्रोतों को ख़त्म नहीं कर सकते. इसका सबसे अच्छा तरीक़ा कर सुधार और मौजूदा क़ानूनों को प्रभावी तरीक़े से लागू करना होगा. पश्चिमी देशों के मुक़ाबले भारत में क़ानून लागू करना हमेशा से ही मुश्किल रहा है.

F. 'बीमारी' का इलाज

इस बीमारी के इलाज के लिए लंबी अवधि की रणनीति की ज़रूरत है और इसे केवल राजनीतिक मजबूरी नहीं मान लेना चाहिए.

भारत ने संयुक्त राष्ट्र की भ्रष्टाचार निरोधी संधि का हस्ताक्षर किए हैं. लेकिन अब तक इस संबंध में कोई क़ानून नहीं बने हैं.

पिछली सरकार ने जिन विधेयकों का प्रस्ताव दिया था, वो कभी भी संसद के दोनों सदनों में पेश नहीं हो सके.

भारत को उस काले धन को रोकने की ज़रूरत है जो क़ानूनी ख़ामियों के चलते बन रहा है.यदि ऐसा नहीं होता तो भारत विदेशी बैंकों ही ध्यान लगाता रहेगा और कर चोर इस काले धन को किसी और बाज़ार या देश में ले जाना शुरू कर देंगे.

Golden Research Thoughts
ISSN 2231-5063
Impact Factor : 2.2052 (UIF)
Volume-4 | Issue-5 | Nov-2014 Available online at www.aygrt.isrj.org

‘अकेले अरविंद को हराने के लिए 300 से ज्यादा 'सांसद' दिल्ली आएंगे '',इतना काँप क्यो रही है भाजपा?ईमानदारी से इतना भय क्यों है आखिर एस बात पर गौर करने की जरुरत भी हैं एक शोधार्थी होने के नाते मेरा विश्लेषण मानना हैं कि में एस खबर का पुरजोर समर्थन करते हुए आपको बता देना चाहती हूँ कि केजरीवाल कि बातो पर विश्वास , समर्थको से भी अधिक उसके विरोधी (भ्रष्टचारी) करते है, तभी तो पिछली बार सरकार बनने से पहले ही पुरानी फाइले फटने लगी, अधिकारी ट्रांसफर चाहने लगे, सारे दलाल घबराने लगे।
ऐ बी वी पी न्यूज खबर दिनांक २० नबम्बर २०१४ की बात हैं
मीडिया शोध के तहत अंतर्वस्तु विश्लेषण ओपेनियन पोल पद्धति से पता चला हैं

मोदी सरकार काले धन मामले के सभी नाम उजागर करेगी ?

हाँ	356 Votes
नहीं	162 Votes
पता नहीं	95 Votes

कितनी मुश्किल है काले धन की वापसी

Golden Research Thoughts
ISSN 2231-5063
Impact Factor : 2.2052 (UIF)
Volume-4 | Issue-5 | Nov-2014 Available online at www.aygrt.isrj.org

.काले धन की जांच में सामने आए विरासत में मिले बैंक खाते: विदेशों में जमा काले धन की जांच में बड़ी संख्या में लोगों के ऐसे खातों का मुद्दा भी उभर रहा है जो परिवार के सदस्यों या पूर्व में गठित ट्रस्टों या कंपनियों से विरासत में मिले हैं। उधर भारत ने स्विट्जरलैंड से वहां के बैंकों में भारतीयों द्वारा कथित रूप से जमा बेहिसाब धन के बारे में और जानकारी मांगी है। इस समय सैकड़ों की संख्या में व्यक्तियों तथा इकाइयों की जांच हो रही जिनके बारे में संदेह है कि उन्होंने एचएसबीसी बैंक की स्विट्जरलैंड की शाखा व अन्य विदेशी बैंकों में कथित तौर पर काला धन जमा करा रखा है। इनमें इनमें उच्चतम न्यायालय में सरकार की ओर से दिए गए 627 नाम भी शामिल हैं। स्विट्जरलैंड ने भारत को जांच में तत्काल सहयोग तथा सूचनाओं के लिए किए गए आग्रह पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। भारतीय अधिकारी ऐसे मामलों में स्विट्जरलैंड सरकार से संपर्क करने से पहले अपनी ओर से जांच कर रहे हैं। भारत सरकार को विभिन्न स्रेतों से जो नाम मिले हैं उनकी पड़ताल से पता चला है कि इनमें काफी संख्या में ऐसे खाते हैं जो मौजूदा खाताधारकों को अपने अभिभावकों या परिवार के अन्य सदस्यों या ऐसे निष्क्रि य न्यासों और कंपनियों से विरासत में मिले हैं जिनका गठन वर्षो पहले किया गया था। इन नामों में एचएसबीसी संबंधी सूची भी शामिल है जो फ्रांस सरकार से मिली है। विरासत में मिले खातों की वास्तविक संख्या का पता नहीं चला है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इनमें से काफी खाते ऐसे हैं जिनके बारे में भारत स्विट्जरलैंड के अधिकारियों से और ब्योरा मांग रहा है। स्विट्जरलैंड पर लंबे समय तक काले धन की सुरक्षित पनाहगाह होने का आरोप लगता रहा है। पिछले महीने स्विट्जरलैंड ने भारत को सभी आवश्यक सहयोग का वादा किया । साथ ही उसने यह भी कहा था कि वह आग्रहों का समयबद्ध तरीके से जवाब देगा या फिर कम से कम जवाब न देने की वजह बताएगा। स्विट्जरलैंड के वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने हाल मेंबर्न से इस तरह की गोपनीय सूचनाओं के खुलासे के लिए संधि के प्रावधानों के बारे में बताया था।

क्षेत्र में पूरी दुनिया को सहयोग किया। स्वराज ने कहा, 'भारतीय मूल के लोगों को पहले ही आजीवन वीजा की सुविधा दे दी गई है। इसके अलावा मॉरीशस को वीजा ऑन अराइवल स्कीम में शामिल करने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी हो जाएगी।' उन्होंने मॉरीशस के लोगों को गुजरात के गांधीनगर में सात से नौ जनवरी तक होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस में शामिल होने का न्यौता भी दिया। सुषमा ने कहा कि भारत में हमेशा आपका स्वागत है।

विश्वै बीबी.खबर सी ट्रांसपेरंसी इंटरनेश समझ नहीं आता अरविन्द को हराने जिताने की बात करते हैं लोग , अरे अरविन्द हारा कब है जो कोई जिताएगा , जिस नौकरी को लात मारा है वो नौकरी चाह कर भी किसी चाय और भठूरे वाले के नसीब नहीं होगा अगर रूपए !

रे वो तो समाज को अ !कमाने होते तो इतना कमाता की रखने का जगह कम पड़ जाता जिताना चाहता ह , ईमानदारी को जिताना चाहता है , गरीब को जीताना चाहता है पर ! ! लोगों को भ्रम हो गया है अपना दुश्मन खुद बन रहे हैं लोग अरविन्द का विरोध करके आम जनता को पता नहीं क्या मिलेगा यूँ तो भारत की राजनितिक व्यवस्था चरमरा गई हैं पूरी तरह ,जनता को मैं यही समझा सकती हूँ कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा ही शासन हैं यह परिभाषा हमेशा हिन्दुस्तान में साक्ष्य रहेगीं ,कानून को कोई नहीं बदल सकता है

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची -----

1. बालकृष्णन, एस (2001): "नागरिकों के लिए एकजुट होना चाहिए
2. भ्रष्टाचार ", भारत, 2 मई के टाइम्स लेख लड़ो:पृष्ठ 3।
3. बारू, संजय (1995): "सुहृद पूंजीवाद: भ्रष्टाचार
4. और उदारीकरण ", टाइम्स ऑफ इंडिया,
5. फ़रवरी 8: 14।
6. बीबीसी (2013): "भारत में पुलिस आशीष नंदी प्रश्न
7. 'जाति कलंक' 'पर, 29 जनवरी, डब्लू डब्लू बीबीसी रिपोर्ट
8. एन. डी. टी. विश्व एशियन समाचार
9. बिदवई (1988) प्रफुल्ल: "उदारीकरण की सीमा से:
10. क्यों विश्व बैंक नुस्खे, "काम नहीं चलेगा भारत, 15 फरवरी के टाइम्स, पी 8।
11. बुकोवंसकी , मालदा (2006): के "खोखलापन
12. इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार विरोधी प्रवचन, "समीक्षा
13. राजनीतिक अर्थव्यवस्था, 13 (2): 181-209।
14. व्यापार और अर्थव्यवस्था (2005): "भ्रष्टाचार की गारंटी"
15. 8 सितंबर, डब्लू डब्लू .बिजनिस इकोनोमिक सन्डे इंग्लिश से हिंदी लेख मेरे द्वारा किया गया आलोचनात्मक विश्लेषण हैं
16. चटर्जी, पार्थ (2011a): राजनीतिक समाज की प्रजातियों:
17. पोस्टकोलोनियल लोकतंत्र में स्टडीज , इसे मेरे द्वारा हिंदी अनुवाद कर साहित्य का पुनरावलोकन किया गया हैं (नई
18. न्यूयॉर्क: कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस)।
19. (2011b): "लोकतंत्र और आर्थिक बदलाव

20. संजय Ruparelia, संजय में भारत "में
21. रेड्डी, जॉन Harriss और स्टुअर्ट Corbridge
22. (एड।), भारत की नई राजनीतिक अर्थव्यवस्था को समझना:
23. एक महान परिवर्तन? (Padstow:
24. रूटलेज), 17-34।-
25. Cockcroft, लारेंस (2010): "ग्लोबल भ्रष्टाचार:
26. एक जंगली हाइड्रा, "विश्व नीति जर्नल,
27. 27 (1): 21 28।
28. Denoon, (1998) डेविड बिहार: "भारतीय आर्थिक में साइकिल
29. उदारीकरण, 1966 1996 ", तुलनात्मक
30. राजनीति, 31 (1): 43 60।
31. ईजेकील, (1994) हन्नान: "उदारीकरण के गुण:
32. लोग ", द टाइम्स को समझाने के लिए कैसे
33. भारत, 23 दिसम्बर: 14।
34. Gallagher, मार्क (1991): रेंट की मांग और आर्थिक
35. अफ्रीका (: वेस्टव्यू प्रेस लंदन) में वृद्धि।
36. Gephart, Malte (2012): का "चुनाव लड़ा अर्थ
37. भ्रष्टाचार: अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय Narratives
38. पराग्वे के प्रकरण ", Giga अनुसंधान कार्यक्रम में:
39. पावर, मानदंडों और प्रशासन में
40. अंतरराष्ट्रीय संबंध, वर्किंग पेपर नहीं 191,
41. वैश्विक और क्षेत्र अध्ययन के जर्मन संस्थान,
42. हैम्बर्ग, जर्मनी।
43. गिरि, सरोज (2011): "भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन
44. और इसकी झूठी विभाजित ", आर्थिक और राजनीतिक
45. साप्ताहिक, 46 (26 और 27): 14 16।
46. गार्जियन नौकरी (2012): "ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल
47. ब्रिटेन कार्यकारी निदेशक ", 16 नवम्बर, देखी गयी

48. गुप्ता, अखिल (2012): लाल टेप: नौकरशाही, स्ट्रक्चरल

49. भारत (लंदन में हिंसा और गरीबी:
50. इयूक यूनिवर्सिटी प्रेस)।
51. गुप्ता, आर सी (1995): "किसका उदारीकरण"
52. 14: भारत, 1 जनवरी के टाइम्स।
53. Harriss-सफेद, बारबरा (1998): "एक एजेंडे में
54. सीमावर्ती, "एक आंदोलन की खोज, 15 (7), http: //
55. www.frontline.in/static/html/fl 1507/150707
56. 90.htm
57. हजारे, अन्ना (2011a): "कांग्रेस के खिलाफ मैं कर रहा हूँ?", 12
58. अक्टूबर, http://annahazaresays.blogspot.co.uk/
59. 2011/10 / AM-मैं-खिलाफ congress.html
60. (2011b): 14 "! का रास्ता एक क्रांति की" अक्टूबर,
61. http: // annahazaresays.wordpress.com/ 2011 /
62. 10/14 / यात्रा का एक-क्रांति-/
63. जाधव, राधेश्याम और सारंग Dastane (2012):
64. "अरविंद केजरीवाल के साथ अन्ना हजारे आत्मविश्वास आरएमएस दरार,
65. उनका अराजनैतिक जन आंदोलन होगा कहते हैं
66. , "आगे बढ़ें टाइम्स ऑफ इंडिया, 19 सितम्बर।
67. जैन, Girilal (1985): "वादा और Fulfi lment: समस्याएं
68. राजीव गांधी मई चेहरा ', द टाइम्स
69. भारत, 6 फरवरी: 8।
70. यूसुफ, Jaimon (2011): "कैसे अन्ना हजारे बन गया
71. एक मीडिया घटना ", सीएनएन आईबीएन, 22 अगस्त,
72. http://ibnlive.in.com/news/how-anna-hazarebecame-
73. एक मीडिया घटना / 177680 3.html
74. काटजू, मार्कंडेय (2012): "मीडिया की भूमिका और
75. अन्ना हजारे के आंदोलन ", सत्यम Bruyat,
76. 9 अगस्त, http: // justicekatju। blogspot.co।
77. ब्रिटेन / 2012/08 / भूमिका के मीडिया और अन्ना hazaremovement।
78. HTML
79. कविराज, सुदीप्ता (2010): भारतीय के trajectories

80. राज्य: राजनीति और विचार (नई दिल्ली: स्थायी
81. काला)।
82. Klitgaard, रॉबर्ट (1988): नियंत्रित भ्रष्टाचार
83. (बर्कले: कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रेस)।
84. कोठारी, रजनी (1986): "जनता, वर्गों और
85. राज्य ", आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 21 (5): 210 16।
86. कुमार, कृष्णा (2011): "राज्य सफाई", आर्थिक
87. और पॉलिटिकल वीकली, 46 (48): 14 17।
88. Laclau, अर्नेस्टो (1996): मुक्ति (एस) (लंदन:
89. उलटा)।
90. Laclau, अर्नेस्टो और Chantal Mouffe (2001): नायकत्व
91. और सोशलिस्ट रणनीति: एक कट्टरपंथी की ओर
92. लोकतांत्रिक राजनीति (लंदन: वर्सो)।
93. Lamont, जेम्स (2011): "एक लाख Mutinies आमंत्रित"
94. फाइनेंशियल टाइम्स, 18 अगस्त।
95. नारायण, (1957) जयप्रकाश: सर्वोदय की एक तस्वीर
96. सामाजिक व्यवस्था (तंजौर: सर्वोदय Prachuralaya)।
97. Nargolkar, वसंत (1975): क्रांति के लिए जेपी के धर्मयुद्ध
98. (नई दिल्ली: एस चांद)।
99. Panagariya, अरविंद (2008): भारत: उभरते
100.विशालकाय (न्यूयॉर्क: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस)।
101.पाणि, Narendar (1996): "भ्रष्टाचार पर ध्यान दें: आर्थिक
102.उदारीकरण और राजनीति ", टाइम्स
103.16: भारत, 19 मार्च के।
104.पटनायक, प्रभात (1985): "राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर
105.आर्थिक 'उदारीकरण', 'सामाजिक वैज्ञानिक की,
106.13 (7/8): 3 17।
107.पॉल, सैमुअल और मनुभाई शाह (1997): "भ्रष्टाचार
108.Sanjivi में लोक सेवा डिलिवरी "में
109.गुहान और सैमुअल पॉल (एड।), भ्रष्टाचार में

110.भारत: लड़ाई (नई दिल्ली के लिए एजेंडा: सार्वजनिक
111.अफेयर्स सेंटर), 144 63।
112.Polzer, तारा (2001): "भ्रष्टाचार: Deconstructing
113.विश्व बैंक प्रवचन ", लंदन स्कूल आफ इकोनॉमिक्स विकास
114.अध्ययन संस्थान वर्किंग पेपर सीरीज कोई 01 18।
115.प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (2012): "भ्रष्टाचार के नाक में दम------
116.मनरेगा के कार्यान्वयन: सरकार ",
117.भारत, 14 जुलाई के टाइम्स।
118.(2013): "अन्ना हजारे जयप्रकाश recreates
119.पटना में नारायण की आभा, Janatantra की शुरूआत
120.मोर्चा ", सीएनएन आईबीएन, 30 जनवरी, http: // सामग्री।
121.ibnlive.in.com/article/30 Jan-2013politics/anna-
122.-JPS-आभा-इन पटना प्रक्षेपण janatantra- recreates
123.मोर्चा-369867 37.html
124.राघवन, आर (2011): "अन्ना हजारे घटना",
125.हिंदू, 8 अप्रैल, नि: //www.thehindu।
126.कॉम / राय / लीड / अन्ना हजारे घटना /
127.article1609185.ece
128.रेड्डी, सी राममनोहर (2001): "लूट राज ',
129.हिंदू, 17 मार्च।
130.रूट, हिल्टन (1997): "के आर्थिक नतीजों
131.भ्रष्टाचार ", टाइम्स ऑफ इंडिया, 20 सितम्बर: 15।
132.रॉय, अरुंधति (2011a): "भ्रष्टाचार है जब
133.देखी गयी अस्पष्ट रूप में ", इंडियन एक्सप्रेस, 30 अप्रैल,
134.http://www.indianexpress.com/news/-whencorruption-
135. देखा जाता है fuzzily- / 783,688 / 0
136.श्मित्ज़, गेराल्ड (1995): "Democratisation और
137.Demystifi कटियन: Deconstructing 'गवर्नेंस'
138.डेविड मूर में विकास प्रतिमान के रूप में "
139.और गेराल्ड श्मित्ज़ (एड।), बहस विकास

140.परिचर्चा (लंदन: पालग्रेव मैकमिलन),

141.59 71।

142.स्कॉट, जेम्स सी (1998): एक राज्य की तरह देख रहा है: कैसे कुछ

143.योजनाएं मानव हालत में सुधार (येल यूनिवर्सिटी प्रेस न्यूयॉर्क) में नाकाम रहे हैं।

144.सेन, मोहित (1999): "नेहरू का विजन:

145.अवादी कांग्रेस कार्यक्रम ",

146.भारत में 9 टाइम्स पत्रिका जनवरी के लेख ।

147.शर्मा, चंचल कुमार (2011): "एक असंबद्ध

148.आर्थिक सुधार स्थिरता का प्रभुत्व थ्योरी:

149.भारत के मामले ", भारत की समीक्षा,

150.10 (2): 126 84।

151.सिंह, एस निहाल (1988): "राजीव और सरकार पस्त",

152.भारत, 10 मई के टाइम्स: 8।

153.सुब्रमण्यम, एन वी (2011): "समझना

154.अन्ना हजारे घटना ", डीएनए भारत, 13

155.अप्रैल, http://www.dnaindia.com/india/analysis_

156.समझ अन्ना हजारे घटना

157._1531257

158.टाइम्स ऑफ इंडिया (1974): "'ईमानदार' जांच के लिए जेपी"

159.अप्रैल 17: 1।

160.(1975a): "पूंजीपतियों के लिए इंदिरा नियम स्वर्ग:

161.जेपी ", 28 जनवरी: 9।

162.(1975b): "अपरिहार्य उर्स सरकार के बदले: जेपी"

163.मई 15: 7।

164.(1979): "जेपी स्वच्छ राजनीति के लिए जेहादी", 9 अक्टूबर:(1984): 26 दिसंबर "राजीव अंतुले दावा खिल्ली उड़ाते हैं":

165.(1985): "भ्रष्टाचार मुख्य समस्या: प्रधानमंत्री"

166.20 जुलाई: 1।

167.(1986): "सरकार छोटी इकाइयों को प्रोत्साहित करेंगे"

168.18 सितंबर: 14।

169.(1987): 9, "हो सकता है कि राजीव जाना चाहिए, भाजपा दोहराया जाएगा":
170.14।-------
171.(1988): "सेंध प्रधानमंत्री की छवि में: सर्वे", 6 जनवरी:
172.17।
173.(1990): 27 दिसंबर "अन्ना हजारे पुरस्कार देता है":
174.3।
175.(1991a): "'अस्वीकृत और उदारीकरण के पतन",
176.मार्च 7: 13।
177.(1991b): "आर्थिक उदारीकरण जाना चाहिए
178.पूर्ण लंबाई: एसोचैम ", 20 जून: 13।
179.(1997a): "हजारे राज्य व्यापी यात्रा पर बाहर सेट,"
180.जुलाई 12: 3।
181.(1997b): "भ्रष्टाचार के लिए मुख्य झटका है
182.इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट: प्रधानमंत्री ", 23 जुलाई: 21।
183.तिवारी (2003): "एना हजारे: भ्रष्टाचार विरोधी प्रचारक
184.भारत ", ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल,
185.मार्च 25, डब्लू .डब्लू .ट्रांसपेरेंसी.ओ आर.जी .इन
186.अवार्ड विनर अन्ना हजारे
187.तिवारी भारत (2011): "वकालत और कानूनी सलाह केन्द्र",
188.ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया, 31 मार्च,
189.विट्ठल, एन (2003): भारत में भ्रष्टाचार: अंधी गली
190.राष्ट्रीय समृद्धि (नई दिल्ली: शैक्षणिक
191.फाउंडेशन)।
192.लकड़ी, जॉन आर (1975): "एक्स्ट्रा संसदीय विपक्ष
193.भारत में: लोकलुभावन आंदोलन के एक विश्लेषण
194.गुजरात और बिहार, नीतिगत मामलों में,
195.पृष्ट 48 (3): 313 34।
196.बोल्फेंसन जेम्स डी (1999): 'गरीबों के लिए वोट ",
197.वाशिंगटन पोस्ट, 10 नवंबर: A39।
198.विश्व बैंक (1997a): विश्व विकास रिपोर्ट

199.1997: एक बदलती दुनिया में राज्य (नई
200.न्यूयॉर्क: विश्व बैंक प्रकाशन)
201.भारत की रिपोर्ट (1997): "भ्रष्टाचार और आर्थिक विकास",
202.बी बी सी लेख ,२०११ देश भ्रष्टाचार से मुकाबला मदद:
203.विश्व बैंक, सितंबर २०११ , की भूमिका: //
204.www1। worldbank। org / publicsector / anticorrupt corruptn / cor02.htm
205.वकुलावार्नाम वी और एस मोतीराम (2011): "राजनीतिक
206.भारत में कृषि संकट के बाद की अर्थव्यवस्था
207.संजय रुपरियला , संजय रेड्डी में 1990 के दशक "
208.जींस हैरिस और स्टुअर्ट क्रोब्रिज (एड), समझौता
209.भारत की नई राजनीतिक अर्थव्यवस्था: एक महान
210.परिवर्तन? (पदेस्तो : रूटलेज), 101 26।